

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र :

वर्ष : १५

अंक : ७

सोमवार

१८ नवम्बर, '६८

अन्य पृष्ठों पर

निवसन : घोषणा का भविष्य ?

इस वादे को क्या समझें ?

—सम्पादकीय ८२

अस्वस्थ चित्त, अशान्ति की परिस्थिति

और पुलिस की जिम्मेदारी —विनोबा ८३

हाथल की ग्रामसभा-२

—अवध प्रसाद ८४

अन्य स्तम्भ

आन्दोलन के समाचार

सामयिक चर्चा

परिशिष्ट

“गाँव की बात”

मध्यावधि चुनाव विशिष्टांक

सम्पादक
राममूर्ति

सर्व सेवा संघ प्रकाशक

राजघाट, वाराणसी-१, उत्तर प्रदेश

फोन

: ४२८५

दण्ड का औचित्य (?)



मैं स्वयं झूठ बोलूँ और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूँ, तो वह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। व्यभिचारी शिक्षक शिष्यों को संयम किस प्रकार सिखायेगा ? मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहनेवाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थपाठ-सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैंने यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टालस्टाय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था।

आश्रम में एक युवक ऊधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसीसे दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता-झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही ऊधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था। पर इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुँचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाँह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफी माँगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुँची, इससे वह नहीं रोया था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता, तो मुझसे निबट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उमर कोई सत्रह साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था। परन्तु मेरे रूल में उसे मेरे दुःख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया। लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने आत्मा का नहीं, बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था।

बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। रूल से (उस युवक को) पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक कर नहीं सका हूँ। इस दण्ड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दण्ड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुःख का ही प्रदर्शन होता, तो मैं उस दण्ड को उचित समझता। पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी।

उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दण्डनीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार लड़के-लड़कियों को आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा।

—मो० क० गांधी

निकसन : घोषणा का भविष्य ?

जो करोड़ों लोगों का विश्वास प्राप्त कर सके वह आदर और बधाई का पात्र तो है ही। जब पड़ोसी को पड़ोसी पर, जाति को जाति पर, और देश को देश पर विश्वास न हो, तो यह बड़ी बात है कि कुछ देशों ने अब भी विश्वास-प्राप्ति की लोकतांत्रिक पद्धति कायम रखी है। रिचर्ड निकसन इस पद्धति से गुजरकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गये हैं। उन्हें चार वर्षों तक अपने बड़े राष्ट्र के जीवन का उत्तरदायित्व निभाना है। निकसन पर अपने देश का ही नहीं, बहुत कुछ सारी दुनिया का सुख और शान्ति निर्भर है। दुनिया के इतिहास में अगले दस वर्ष असाधारण महत्त्व के हैं। अगर अगले दस वर्षों तक दुनिया युद्ध के सर्वनाश से बच सकी, और अपनी असाधारण गति से बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए भरपेट अन्न का प्रबंध कर सकी, तो निश्चित ही सभ्यता नया मोड़ ले सकेगी। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहुत बड़ा अवसर है; अवसर दुनिया के सबसे अधिक समृद्धशाली देश अमेरिका, और उसके सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रपति निकसन के लिए।

निकसन की पार्टी बड़े व्यवसायियों की पार्टी है, 'कन्जर-वेटिव' है। अमेरिका में कन्जरवेटिव की विजय हुई है। उसी तरह इस वक्त रूस में शक्ति उदारवादियों के हाथ में न रहकर स्टालिनवादियों के हाथ में है। फ्रांस में तो दगाल हैं ही, इंग्लैंड का भी मन लेबर पार्टी से खटा होता जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में तो अलग-अलग नामों से फासिस्टवादियों का बोलबाला है ही। जहाँ एक ओर यह हवा है, वहाँ दूसरी ओर युवकों में आज सामाजिक ढाँचे (इस्टैब्लिशमेंट) से असंतोष बढ़ता जा रहा है, और कभी-कभी ऐसा दिखाई देता है कि नयी और पुरानी पीढ़ियों का संघर्ष शायद सारे दूसरे संघर्षों से अधिक भयंकर होगा।

इतिहास के ऐसे सन्दर्भ में निकसन की यह घोषणा बड़े महत्त्व की है कि उनकी सरकार का दरवाजा दलबन्दी का भेदभाव छोड़कर नये लोगों और नये विचारों के लिए खुला रहेगा। वास्तव में राजनीतिक दलवाद अपने में एक जबरदस्त प्रतिक्रियावादी शक्ति बन गया है। अब मनुष्यों द्वारा मनुष्य-समाज की व्यवस्था होनी चाहिए, न कि दलों, डिक्टेटों, जातियों और सम्प्रदायों द्वारा। रिपब्लिकन राष्ट्रपति, डेमोक्रेटिक कांग्रेस, और दोनों की मिली-जुली सरकार : अमेरिका का यह नमूना भारत के लिए अनुकरणीय हो सकता है।

निकसन ऐसे समय राष्ट्रपति हुए हैं जब अमेरिकी समाज में गंभीर दरारें पड़ चुकी हैं, और वह देख चुका है कि भौतिक वैभव एक सीमा के आगे सुख और शान्ति का साधन नहीं है। इतना ही नहीं, अगर वैभव के साथ दूसरे तत्त्व न जोड़े गये, तो वह स्वयं विनाशकारी तत्त्व बन जाता है। काले और गोरे, नये और पुराने, हिंसा और शान्ति, गरीबी और अमीरी आदि के सवाल अमेरिका

में गंभीर हो गये हैं। ये प्रश्न राजनीतिक स्तर पर कदापि हल होंगे। अगर हल होंगे तो मानवीय स्तर पर। नीग्रो लोगों ने निकसन को वोट नहीं दिया है। वैसे जैसे वर्णवादी को भी १४ प्रतिशत वोट मिल गये हैं! ऐसी हालत में निकसन को नये सिरे से पूरे राष्ट्र का विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा। वे किन मानवीय गुणों से ऐसा करते हैं, इस पर विश्वशान्ति की दिशा में उनकी सफलता निर्भर करेगी। जरूरत इस बात की है कि अमेरिका के गोरे अपने कालों का विश्वास प्राप्त करें, और अमेरिका साम्यवाद का भय छोड़कर आत्मविश्वास प्राप्त करे। विश्वास के बिना अमेरिका स्वयं वर्ण-संघर्ष का शिकार होगा, और दुनिया में तनाव और युद्ध का कारण बनेगा। उसकी अपनी भयमुक्ति बहुत कुछ दुनिया को भयमुक्त कर सकेगी। निकसन के नेतृत्व में अमेरिका के अगले चार वर्षों का इतिहास इस विश्वास और आत्मविश्वास का प्रयोग होगा। हमारी हार्दिक शुभकामना निकसन के साथ है।

इस वादे को क्या समझें ?

अगर गोवा में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक ने नशाबन्दी के प्रस्ताव को साफ-साफ अस्वीकार कर दिया होता तो उसे कम-से-कम ईमानदारी का यश मिल जाता। लेकिन उसने अस्वीकार भी नहीं किया, और स्वीकार भी किया तो इस तरह कि अस्वीकार करने से अधिक कुछ हुआ नहीं। गांधी का भूत कांग्रेस को रह-रहकर सताता रहता है। कांग्रेस अन्दर से चाहे भी कि किसी तरह भूत से जी छूट जाय, तो छूटे कैसे? भूत मामूली नहीं है!

सात साल में नशाबन्दी होगी, लेकिन योजना बनेगी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर। नशाबन्दी को लेकर कांग्रेस की राजनीति कहाँ तक जा चुकी है, इसे हर एक जानता है, और कांग्रेस को लेकर देश की राजनीति कहाँ पहुँच चुकी है, इसे भी हर एक जानता है। सात वर्षों में ८४ महीने होते हैं, और महीने में ३० दिन। क्या इतने दिन इस देश की आत्मा इसी तरह पड़ी सोती रहेगी, और उसके साथ खिलवाड़ होता रहेगा?

नशाबन्दी किसे चाहिए—गांधी को या इस देश की जनता को या यहाँ की सरकारों को? और, इस देश में भी किसको? गांधी, जो हाड़-मांस का आदमी था, उसे जो करना था वह कर गया, जो लेना था ले गया। अब जो कुछ करना हो इस देश की जनता को सामने रखकर करना चाहिए—करोड़ों की संख्या में गरीब, पीड़ित, और पसीना बहानेवाली जनता को। बावजूद सारे दलों और नेताओं के अगर अपनी मौत के इक्कीस वर्ष बाद आज भी गांधी उस जनता का प्रतीक और प्रतिनिधि बना हुआ है तो इसमें उसका क्या दोष है? क्या आज तक कोई भी यह सिद्ध कर सका है कि उस जनता को 'सरकारी' शराब की जरूरत है? सरकार को शराब टैक्स के लिए चाहिए, लेकिन क्या यह बात मानने लायक है कि जनता को शराब पिलाकर बरबाद करने का अधिकार जनता के वोट से बनी किसी सरकार को है? इस देश की जनता खुद जितना

और पुलिस की जिम्मेदारी

• विनोबा

आजादी के बाद बीस साल हो गये। लोगों में चिन्त की स्वस्थता दीखती नहीं। उसमें कई कारण मिल गये हैं। देश बड़ा है। अनेक भाषाएँ, अनेक धर्म, जाति देश में हैं। फिर इसमें अनेक पक्ष भी शामिल हुए हैं—राजनैतिक पक्ष। परिणामस्वरूप देश में जगह-जगह समस्याएँ खड़ी हैं। जगह-जगह किसी-न-किसी निमित्त से दंगे हुआ करते हैं। दंगे के लिए सिर्फ बाहर का कोई निमित्त होता है, इतनी ही बात नहीं। इसका मूल कारण तो यह है कि हमारे चिन्त में समाधान नहीं है। जहाँ चिन्त में असमाधान होगा वहाँ उसका कभी-न-कभी स्फोट होगा। यह बिलकुल स्वाभाविक है। ऐसी हालत में पुलिस का काम बहुत महत्त्व का भी हो जाता है और कठिन भी। ऐसा कठिन कार्य करनेवाली यह जमात है। उस लिहाज से उनको क्या वृत्ति रखनी होगी, इसबारे में हमारे विचार हम सामने रखेंगे।

बाबा का काम बड़ा आसान है। अगर कोई मारता-पीटता है तो हमने तय कर लिया है मार खाने का, मारने का नहीं। तो इस प्रकार से हम अगर मार खाते हैं तो वह हमारी मर्जी की बात है। उस पर कोई 'जुडिशियरी' (तहकीकात) नहीं हो सकती। हमारे खिलाफ उस सम्बन्ध में कोई

तहकीकात नहीं होगी और हमें कोई पूछेगा नहीं कि मार क्यों खाया। वह हमारे हाथ की बात है। हम मार खायेंगे और कभी मारेंगे नहीं, भले मर भी जायेंगे।

फिर मिलीटरी का काम भी बड़ा आसान है, क्योंकि उनको मारने का हक होता है। उनको हुकुम रहता है 'शूट' करने

का। उनकी भी तहकीकात नहीं होती। वे अगर शूट करते हैं तो वहाँ 'जुडिशियरी ऐक्शन' का सवाल नहीं आयेगा। बहुत विशेष प्रसंग हो तो मालूम नहीं ऐसा सवाल आ सकता है और उसकी विशेष तहकीकात हो सकती है। लेकिन सामान्यतया यह सवाल पैदा नहीं होता, उनको मारने का अधिकार है। तो हमारे जैसे का, जिसने अहिंसा का व्रत लिया है और परिणाम को न देखते हुए हमारा फर्ज है न मारने का, उसका काम आसान है और मिलीटरीवालों का, जिनको मारने का अधिकार है।

पुलिसवालों का काम बहुत कठिन है। प्रथम तो उनको शांति का काम करना होगा, दंगे न हो इसलिए गाँववालों से परिचय रखना होगा। साथ-साथ प्रेम से बरतना होगा। गाँव में अन्दर-अन्दर बात चल रही है, उसको जान लेना, गाँववालों को सावधान करना, यह जो शान्ति-सैनिक का काम है वह उनको करना पड़ता है। अगर उतने से नहीं निभा और अशान्ति फूट पड़ी तो

शराब पीना नहीं चाहती उससे कहीं ज्यादा उसे योजनापूर्वक शराब पीना सिखाया जा रहा है। कौन सिखा रहा है? वह सरकार जो हमारे वोट से बनती है, और हमारे टैक्स से चलती है! इससे भी ज्यादा कांग्रेस की सरकार जिसके पास देशप्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है—गांधी का नाम!

डा० सुशीला नैयर के प्रस्ताव में वकिंग कमिटी की ओर से संशोधन पेश करते हुए भूतपूर्व खाद्यमंत्री और मद्रास कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष सुब्रमण्यमजी ने कहा कि इस देश में पूर्ण नशाबन्दी कभी नहीं हो सकती। बिलकुल ठीक! इस दुनिया में कौनसी अच्छी चीज कभी पूर्ण होगी? लेकिन क्या अपूर्णता की आड़ में कभी किसी सरकार को यह अधिकार भी होगा कि वह अच्छाई की ओर बढ़नेवाले समाज को खींचकर बुराई के गड्ढे में ढकेल दे? इतना मान लेने में किसीको क्या कठिनाई है कि सरकार खुद शराब और नशे का व्यापार न करे? क्या कठिनाई यह है कि प्याले का जायका मिल गया है? या, यह है कि ठीकेदारों का पैसा राजनीति के बजट की एक बहुत बड़ी मद है? या, सबसे ज्यादा यह है कि सत्ता के नशे में जनता के हित और देश के भविष्य का ध्यान ही नहीं रह गया है? अगर एक बार सरकार पतन के व्यापार से हट जाय तो सुधारक इस प्रश्न का उत्तर दे लेगा कि नशा स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, या कितना नैतिक-अनैतिक है। देश के घर-घर में भद्रियाँ खुल जायँ उसे यह शायद कबूल होगा, लेकिन एक भी 'सरकारी' दुकान चले, यह मान्य नहीं होगा। इस प्रसंग में विदेशी यात्रियों का नाम लेना बेकार है। और यह कहना कि देश का नशा

युवक गांधी के प्रभाव से अलग और उसकी 'खत्तों' से विमुख है, बुद्धि का दिवालियापन है। सचमुच, युवक सबसे अधिक विमुख उन लोगों से है जो उसके कल्याण के ठीकेदार बने हुए हैं! और मजदूरों का नाम लेना तो साफ-साफ क्रूर व्यंग्य है।

क्या गोवा के बाद यह मान लिया जाय कि कांग्रेस समाज-रचना की शक्ति खो चुकी है? वहाँ मद्यनिषेध जैसे बड़े रचनात्मक कार्य के बारे में जो रख बरता गया उससे दूसरा क्या नतीजा निकाला जाय? लेकिन अकेली कांग्रेस ही क्यों? दूसरी पार्टियों का ही उससे भिन्न क्या हाल है? वास्तव में हमारे देश की पूरी राजनीति रचनात्मक शक्ति खो चुकी है। वह 'स्टेटस्को' को नहीं छोड़ सकती।

क्या डा० सुशीला नैयर इस स्थिति को नहीं जानती थीं? अगर जानती होतीं तो उन्होंने अपने प्रस्ताव में संशोधन स्वीकार कर क्रान्तिकारी सुधार का पक्ष कमजोर न होने दिया होता। लेकिन न जानने की, या जानते हुए भी चूक जाने की, जिम्मेदारी उनकी ही मानी जायेगी।

गोवा में जो कुछ हुआ उसमें इतनी अच्छाई तो है ही कि जनता को यह समझ लेने में मदद मिलेगी कि उसके स्थायी हित अब राजनीति के हाथों में सुरक्षित नहीं हैं। और सुधारकों को भी यह समझ लेना चाहिए कि हमारे समाज के प्रश्न लोकशक्ति से ही हल होंगे, दूसरी किसी शक्ति से नहीं। उसे बनाना ही हमारा मुख्य रचनात्मक कार्य होना चाहिए। सत्ता तब सुनेगी जब समाज की शक्ति बनेगी। नशाबन्दी का प्रश्न लोगों को 'पवित्र' बनाने का ही नहीं, उनके जीवन-मरण का है; शोषण-मुक्ति का है; उनके व्यक्तित्व की रक्षा का है। •

उनको प्रसंगानुसार लाठीचार्ज भी करना पड़ता है। और जरूरत पर बन्दूक भी चलानी पड़ती है। और उसमें उनको शांत वृत्ति रखनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा शक्ति से न बरते, और काम पूरा बनना चाहिए। इस वास्ते 'एफिशिएंसी' भी हो, और ज्यादाती भी न हो। प्रथम जरा-सा धाक दिखाकर काम होता हो तो ठीक। नहीं तो जितनी जरूरत है उतना पीटना—कम नहीं। ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा पीटा ऐसा लगा तो तुरन्त 'इंक्वायरी' होगी और सजा भी हो सकती है। इसलिए पुलिस का काम अत्यन्त कठिन है। इसका मतलब उनको चित्त में क्षोभ नहीं होने देना चाहिए। यह पुलिस का कर्तव्य है, हर हालत में चित्त को शान्त रखना, चित्त बैलेंस में रखना। परिस्थिति का ठीक नाम लेकर तदनुसार पीछे हटना पड़े तो पीछे हटना। आक्रमण करना पड़े तो आक्रमण करना। यह सारा बिलकुल गणित-शास्त्र के अनुसार करना होगा। इसलिए चित्त में क्षोभ हो जाय तो कहीं ज्यादाती भी हो जायेगी।

हमने सहज पूछा था कि पुलिसवालों के पास 'गीता प्रवचन' होखी है या नहीं। इसलिए गीता पास होनी चाहिए कि गीता ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर लड़ना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को कहा कि लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन कैसे लड़ना ? निबैर होकर लड़ना, यानी चोभरहित होकर लड़ना। गुस्सा नहीं करना, वैर-भाव नहीं रखना। ऐसी सारी समत्व बुद्धि रखकर लड़ना। जैसे कोई सर्जन होता है। वह आपरेशन करता है, मरीज का पेट काटता है। और वह उसके कल्याण की कामना से करता है। उस समय उसके चित्त में चोभ नहीं रहता, वैर, गुस्सा नहीं रहता। उसी प्रकार से पुलिस को काम करना चाहिए। तो गीता की यह तालीम हर पुलिस को मिलनी चाहिए। अगर मेरी चली तो मैं हर पुलिस को गीता समझाऊँगा। इसलिए हमने पूछा था कि कितने पुलिसों के पास 'गीता प्रवचन' है ? मैं मानता हूँ कि हर पुलिस को वह किताब पढ़नी चाहिए। आपका काम बिलकुल कठिन काम है—जैसे कोई सरकस होती है। उसमें एक तार पर चलना पड़ता है—बड़ी कुशलता से, सावधानीपूर्वक।

भुकाव इधर भी न जाय और उधर भी न जाय। बिलकुल बीच में समतोल होकर चलना पड़ता है। तो आपका काम उस प्रकार का है।

आरक्षी अधिष्ठाक ने हमसे सवाल पूछा है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हिंसा के क्षेत्र और असर दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस की स्थिति अत्यन्त कठिन हो जाती है। तो क्या करना चाहिए ?

इसका निराकरण करना हो तो पुलिस को—नम्बर एक : सब पक्षों से, सब धर्मों से, सब पंथों से, सब गुटों से अलग रहना चाहिए। चाहे पुलिस का अपना कोई धर्म हो, अपना विचार हो, उसको अपने काम में उन सबसे मुक्त रहना चाहिए। आप विष्णु के भक्त हैं तो अपने घर में भले विष्णु की प्रार्थना करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह की नमाज पढ़ें। क्रिश्चियन हैं तो चर्च में जायें। लेकिन फलाना मनुष्य मुस्लिम है, हिन्दू है या क्रिश्चियन है, इसका विचार आपको करना नहीं है। सामने मानव खड़ा है यही एक भावना रखनी है। सब धर्मों से अलिप्तता रखना—अपना-अपना धर्म होते हुए भी। नंबर दो : भिन्न-भिन्न राजनैतिक पक्ष होते हैं। और कई कारण होते होंगे, जिससे पोलिटिकल पार्टियाँ उकसाती हैं। ऐसी हालत में पुलिसवालों को चाहिए कि वे पक्ष-मुक्त रहें। उनको हर प्रकार से पक्षमुक्त होना अत्यन्त लाजिमी है। यह मानी हुई बात है कि सरकारी सेवकों का सब पक्षों से मुक्त होकर, धर्म, जाति आदि भेदों से परे होकर समाज की सेवा करनी होती है। तटस्थ बुद्धि से मानवता की हैसियत में सेवा का काम करना होता है। आप समाज के उत्तम सेवक हैं।

'आरक्षी' कितना सुन्दर शब्द है ! 'आरक्षी' यानी रक्षा करने का जिनका जिम्मा है, ऐसा जिम्मेवार रक्षक। बहुत ही सुन्दर संज्ञा है। रक्षक को भी समय पर डण्डा लेना पड़ता है, यह अलग बात है, लेकिन उसकी तटस्थ वृत्ति है, उससे उसको हटना नहीं चाहिए और पोलिटिकल पार्टियों का असर अपने दिमाग पर पड़ने नहीं देना चाहिए। यह वृत्ति सब जायेगी तो काम में सहूलियत होगी।

दूसरा सवाल पूछा है कि पुलिस का काम ग्रामदान और शान्ति-सेना आदि कामों में क्या हो सकता है ?

बहुत माकूल सवाल पूछा है। प्रधानतया पुलिस शान्ति-सैनिक हैं और 'प्रिवेन्शन इज बेटर देन क्यूअर।' दंगे होने के बाद पुलिस वहाँ जायेगी उसके बजाय दंगे न हो, इसका खयाल करेगी तो वह अधिक लाभदायी होगा। अन्यथा शान्ति के लिए दमन करना होगा। इसलिए गाँव-गाँव से परिचय रखें। अब जो ग्रामदानी गाँव होंगे उनको बनाने में भी पुलिस की मदद हो सकती है। ग्रामदान के बाद हर गाँव में ग्रामसभा बनानी होगी, जमीन का बँटवारा करना होगा। भूमिहीनों को प्रेम से जमीन देनी होगी। और सरकार से ग्रामदान मान्य करवाना होगा। उसके बाद गाँव-गाँव में शान्ति-सैनिक खड़े करने होंगे। मान लीजिए, गाँव की लोक-संख्या हजार हो यानी २०० घर हों, तो उस गाँव में १० शान्ति-सैनिक हों। और उनको मैंने यही बताया कि गाँव में ऐसी हालत पैदा करनी चाहिए कि पुलिस को गाँव में आने की कोई जरूरत ही न पड़े। मान लीजिए, गाँव में कोई झगड़ा पैदा हो तो गाँववालों को अपनी कोर्ट बनानी चाहिए और उसमें मतभेद दूर करके दोनों पक्षों का समाधान कराना चाहिए। अब कोई क्रिमिनल केस हो तो पुलिस को आना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी झगड़ों के लिए उसका समाधान गाँववाले अन्दर-अन्दर ही करें और पुलिस को गाँव में न आना पड़े, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। तो पुलिस का काम आसान हो जायेगा। यह हम गाँव-गाँव में समझा रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा समय जायेगा। तो यह जो प्राथमिक काम है गाँवों में करने का, उसमें भी पुलिसवाले मदद दे सकते हैं। गाँववालों को समझा सकते हैं। ग्रामदान के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि 'ला एण्ड ग्रांडर' के लिहाज से यह काम बहुत महत्त्व का है। यह नहीं कि वे अपना डण्डा दिखाकर लोगों से हस्ताक्षर लें। लेकिन प्रेम से पेश आयें, और विचार समझाकर लोगों को प्रेरित करें। पुलिस-अधिकारियों के साथ हुई चर्चा से। समन्वय-आश्रम, बोधगया, २५-१०-६८

ग्राम-निर्णय

(कार्य-पद्धति और वैचारिक परिवर्तन : एक अध्ययन)

ग्रामसभा में छोटे प्रश्न से लेकर बड़े-से-बड़े प्रश्न पर विचार किया जाता है। ग्रामसभा ने किस प्रकार के निर्णय कैसे किये, उसकी जानकारी प्राप्त करने पर निर्णय की प्रक्रिया तथा काम के ढंग का अंदाज आसानी से लग जायगा। यहाँ हम ग्रामसभा निर्माण होने से लेकर अबतक हुए कुछ निर्णयों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि महत्त्व के हैं :

तारीख	निर्णय	पद्धति
२५-१२-६१	(१) कम-से-कम दो माह में एक बैठक हो।	सर्वसम्मति
	(२) ५१ लोगों का कोरम हो।	"
	(३) बिना इजाजत के जो बाड़े (काटों का धेरा) लगे हैं, उनकी जाँच हेतु कमेटी का निर्माण।	"
१७-१-६२	(१) श्री मंजीशिवजी ने विद्यालय-निर्माण हेतु ग्रामसभा को २५ हजार रुपये दान में दिये। विद्यालय का नाम 'श्री मंजीशिवजी विद्यालय' रखा गया।	"
४-२-६२	(१) चर्मोद्योग, तेलघानी, भट्टा, रेशा-उद्योग हेतु सरकार के साथ कार्य-वाही का निर्णय।	"
२१-३-६२	(१) कुएँ का पानी साफ रखने, कूड़ा-करकट एक स्थान पर जमा करने, पेशाबवर निर्माण करने, जंगल काटने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय।	"
१७-५-६२	(१) (क) लगान सभी लोग समय पर जमा करें, जिससे ग्रामसभा के कोष पर बोझ न पड़े। (ख) ग्रामसभा समय पर लगान जमा कर सके इसलिए कुआँवालों से १०० रु०, ७ बीघावालों से ५ रु०, १० बीघा या उससे अधिकवालों से १५ रु० अग्रिम जमा कराया जाय।	सर्वानुमति
	(२) मंदिर-खर्च के लिए प्रति १ रु० लगान पर २० पैसा अतिरिक्त कर लगाया जाय।	मुक्त चर्चा हेतु छोड़ दिया गया। (१ माह का समय)
२६-५-६२	(१) भूमि-वितरण : (क) कुएँ के पास एक परिवार की ५० बीघे से जितनी अधिक	सर्वानुमति
	(ख) जिसके पास बँल नहीं हैं और वह खेती करना चाहता है, तो उसे ७ बीघा जमीन दी जाय।	"
	(ग) एक जोड़ी बँलवाले को १२ से १५ बीघा जमीन दी जाय।	"
	(घ) प्रत्येक बालिग, जो खेती करने को इच्छुक हो, योग्य हो, उसे उक्त हिसाब से जमीन दी जाय।	"
	(च) बँटाई पर खेती कोई नहीं करा सकता। मजदूर रख सकता है।	"
	(छ) दूसरे गाँववालों को खेती न करने दिया जाय।	"
२५-११-६२	(१) मंदिर हेतु २० पैसा अतिरिक्त लगान का प्रस्ताव मुक्त चर्चा के बाद वापस ले लिया गया।	"
	(२) मंदिर-खर्च के विचारार्थ कमेटी का निर्माण।	सर्वानुमति
१४-५-६३	(१) सामूहिक खेती प्रारंभ की जाय।	"
	(२) सामूहिक खेती की आय मंदिर खाते में जमा रहे।	"
	(३) स्कूल में 'अध्यापक-भवन' का निर्माण हो।	"
६-१-६४	(१) मकान और कुएँ के लिए ग्रामसभा सर्वसम्मति लोगों को जमीन दें, जिसकी कीमत समतल जमीन की ५ पैसा और असमतल की ३ पैसा प्रति वर्गफुट ली जाय।	"
१६-६-६४	(१) सन् १९६२ में तय हुई भूमि-वितरण सर्वसम्मति नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कमेटी का निर्माण।	"
५-२-६५	(१) कार्यकारिणी समिति के दूसरे सत्र का चुनाव सम्पन्न हुआ।	"
	(२) कार्यकारिणी १० की हो, यह प्रस्ताव वापस और १५ की हो, यह मान्य।	"
	(३) कार्यकारिणी का कोरम ५ का हो।	सर्वसम्मति
५-६-६५	(१) श्रमदान से विद्यालय-भवन का निर्माण प्रारंभ।	"
	(२) भूमि-वितरण की नीति पर विचार।	"
	(३) मेड़बन्दी की माँग।	"

तारीख
१७-१-६६

www.vinoba.in

निर्णय

पद्धति

दैनंदिनी १९६६

६-२-६६

- (१) मेड़बन्दी प्रारंभ की जाय । सर्वसम्मति
- (२) जागीरदारी मुआवजा बांड १९,२०० " ६० को अलग जमा किया जाय, उसे व्यक्तिगत संपत्ति न मानी जाय ।*
- (१) 'अध्यापक-निवास' के लिए ग्रामकोष की रकम में से एक निश्चित रकम दी जाय ।
- (२) इधर-उधर रखी लकड़ी ग्रामसभा जमा कर ले ।
- (३) गांधी जन्म-शती मनाने का निर्णय । "

-अवध प्रसाद

गांधी-शताब्दी के अवसर पर १९६६ की जो दैनंदिनी हमारे यहाँ से प्रकाशित की गयी है उसका स्टाक बहुत ही कम बचा है, अतः वे संस्थाएँ, जो दैनंदिनी मँगाना चाहती हैं, रकम अप्रिम भिजवाकर या १०० पी० या बैंक के मार्फत प्राप्त कर लें, अन्यथा गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी निराशा होना पड़ेगा ।

आकार

मूल्य प्रति

क्राउन ७१" × ५"

३.००

डिमाई ६" × ५१"

३.५०

५० या उससे अधिक दैनंदिनियाँ एकसाथ मँगाने पर २५ प्रतिशत कमीशन और ग्राहक के निकटतम स्टेशन तक दैनंदिनी फ्री डिलेवरी से भिजवायी जाती है ।

संचालक

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी-१

* उक्त रकम सरकार की ओर से गाँव के तीन व्यक्तियों को जागीरदारी बांड के रूप में मिली थी ।

गांधी शताब्दी वर्ष १९६६-६६

गांधी-विनोबा का ग्राम-स्वराज्य का संदेश गाँव-गाँव, घर-घर पहुँचाइए और जन-जन को उसके लिए कृत-संकल्प कराइए । सच्चे स्वराज्य का अब यह ही रास्ता है । इस निमित्त उपसमिति द्वारा निम्न सामग्री पुरस्कृत/प्रकाशित की गयी है :-

पुस्तकें—

- (१) जनता का राज्य—लेखक : श्री मनमोहन चौधरी, पृष्ठ ६२, मूल्य २५ पैसे । ग्रामदान-आन्दोलन की सरल-सुबोध जानकारी ।
- (२) Freedom for the Masses—'जनता का राज' का अनुवाद, पृष्ठ ७६, मूल्य २५ पैसे ।
- (३) शान्तिसेना परिचय—लेखक : श्री नारायण देसाई, पृष्ठ ११८, मूल्य ७५ पैसे । शान्तिसेना विचार, संगठन, कार्यक्रम आदि की जानकारी देनेवाली, हर शान्ति-प्रेमी नागरिक के पास रखी जाने योग्य ।
- (४) हत्या एक आकार की—लेखक : श्री ललित सहगल, पृष्ठ ६६, मूल्य ६० ३.५० । गांधीजी के हत्यारे के हृदय में हत्या से पूर्व चलनेवाले अन्तर्द्वन्द्व का प्रभावपूर्ण सशक्त चित्रण ।
- (५) A Great Society of small Communities—लेखक : सुगत दासगुप्ता, पृष्ठ ७८, मूल्य ६० १०.०० । क्रान्ति में ग्रामदान-आन्दोलन का स्थान तथा ग्रामदानी गाँवों के सन्दर्भ में आन्दोलन की गतिविधि का विवेचन और समीक्षा ।

वितरण और प्रदर्शन की सामग्री—

फोल्डर—(१) गांधी, गाँव और ग्रामदान (२) गांधी, गाँव और शान्ति (३) ग्रामदान क्यों और कैसे ? (४) ग्रामदान क्या और क्यों ? (५) ग्रामदान के बाद क्या ? (६) ग्रामसभा का गठन और कार्य (७) गाँव-गाँव में खादी (८) सुलभ ग्रामदान (९) देखिए : ग्रामदान के कुछ नमूने ।

पोस्टर—(१) गांधी ने चाहा था : सच्चा स्वराज्य (२) गांधी ने चाहा था : स्वावलम्बन (३) गांधी ने चाहा था : अहिंसक समाज (४) ग्रामदान से क्या होगा ? (५) गांधी जन्म-शताब्दी और सर्वोदय-पर्व ।

सामग्री मर्यादित रूप में निम्न स्थानों से प्राप्त की जा सकती है :-

- (१) गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी जन्म-शताब्दी समिति), डुकलिया भवन, कुँदीगरों का भैंरों, जयपुर—३ (राजस्थान) । (२) सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१ (उत्तर प्रदेश)

राष्ट्रीय गांधी जन्म-शताब्दी समिति की गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति द्वारा प्रसारित

उत्तर प्रदेश में दो नये जिलादान की सम्भावना

वाराणसी, ६-११-'६८। उत्तराखण्ड के कर्मठ कार्यकर्ता श्री चखड़ी प्रसाद भट्ट ने एक भेट में हमारे प्रतिनिधि को बताया कि उत्तरकाशी जिले के बाद उत्तराखण्ड में दूसरा, उत्तर प्रदेश में तीसरा और भारत में ग्यारहवाँ जिलादान चमोली का १४ नवम्बर '६८ तक पूर्ण हो जाने की पूर्ण आशा है। इसके लिए कार्यकर्ता अविरत प्रयत्न कर रहे हैं। आपने कहा कि जिलादान समर्पण-समारोह का आयोजन शीघ्र ही किया जायेगा।

वाराणसी जिले में भी जिलादान के लिए प्रयत्न जारी है। ग्रामदान-अभियान के एक प्रमुख कार्यकर्ता श्री अमरनाथ मिश्र ने जिले में ग्रामदान-प्राप्ति की प्रगति का विवरण देते हुए कहा कि जिले के कुल २२ विकास प्रखण्डों में से १० प्रखण्डों का दान हो चुका है। जिले की ३०% जनसंख्या ग्रामदान में शामिल हो चुकी है। वाराणसी जिले का जिलादान कराने के लिए क्षेत्र के वयोवृद्ध कार्यकर्ता पं० रामसुरत मिश्र के नेतृत्व में काम चल रहा है, और जिले की रचनात्मक संस्थाएँ पूरा सहयोग दे रही हैं।

'प्रदेशदान' शताब्दी-वर्ष का प्रेरणा-सूत्र : मध्यप्रदेश गांधी-शताब्दी-सम्मेलन का प्रस्ताव

२६ अक्टूबर को प्रदेशीय गांधी-शताब्दी-सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा शताब्दी-वर्ष में 'प्रदेशदान' का संकल्प करने और उसे पूरा करने का निश्चय जाहिर किया है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय गांधी जन्म-शताब्दी समिति द्वारा स्वीकृत नौसूत्री कार्यक्रम को अलग-अलग न मानकर सभी को एकसाथ और समग्र रूप में मानकर काम करने का निवेदन किया गया है, और प्रान्त की जनता से तन, मन, धन से सहयोग की प्रार्थना की गयी है।

गया जिले की ४० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामदान में शामिल

बोधगया : १० नवम्बर, '६८। गया जिले के लगभग ७०-७५ प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक सभा में—जो विनोबा को बोध-गया से विदा देने के लिए आयोजित की गयी थी—यह आशा व्यक्त की गयी कि १७ नव-म्बर, '६८ तक गया का काम पूरा हो जायेगा। इस अवसर पर विनोबाजी ने अब तक हुए काम की प्रगति के लिए सबको धन्यवाद देते हुए कहा कि साम्यवाद और सम्प्रदायवाद की शक्तियाँ दुनिया में तेजी से ध्वंसात्मक परि-स्थिति का निर्माण कर रही हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ अच्छे काम से क्रान्ति नहीं होगी।

और अगर क्रान्ति नहीं हुई, यथास्थिति बनी रही तो भारत का खात्मा ही हो जायेगा। इसलिए क्रान्ति के इस काम में पलभर की भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए।

आचार्य विनोबा ने वाराणसी में हुए छात्र-पुलिस संघर्ष की चर्चा करते हुए कहा कि आज सारी दुनिया के विद्यार्थियों में एक नया जागरण हो रहा है, भारत में भी वह हुवा विद्यार्थियों को प्रभावित कर रही है। ऐसी स्थिति में आचार्यकुल द्वारा सही दिशा का निर्देशन होना चाहिए। आपने भारत सेवक समाज, साधु-समाज आदि अच्छे कामों में लगी संस्थाओं से निवेदन किया कि वे ग्रामदान के क्रान्तिकारी काम में लगे, क्योंकि दुनिया में अशान्ति की ताकतें तेजी से बढ़ रही हैं।

खादी और ग्रामोद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं

इनके सम्बन्ध में पूरी जानकारी के लिए

खादी ग्रामोद्योग

(मासिक)

पढ़िये

जायति

(पाक्षिक)

(संपादक—जगदीश नारायण वर्मा)

हिन्दी और अंग्रेजी में समानांतर प्रकाशित

प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष।

विश्वस्त जानकारी के आघार पर ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्य-ताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका। खादी और ग्रामोद्योग के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगीकरण की सम्भावनाओं तथा शहरीकरण के प्रसार पर मुक्त विचार-विमर्श का माध्यम।

ग्रामीण धंधों के उत्पादनों में उन्नत माध्यमिक तकनालाजी के संयोजन व अनुसंधान-कार्यों की जानकारी देनेवाली मासिक पत्रिका।

वार्षिक शुल्क : २ रुपये ५० पैसे

एक अंक : २५ पैसे

प्रकाशन का बारहवाँ वर्ष।

खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों सम्बन्धी ताजे समाचार तथा ग्रामीण योजनाओं की प्रगति का मौलिक विवरण देनेवाला समाचार पाक्षिक। ग्राम-विकास की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करनेवाला समाचार-पत्र।

गांवों में उन्नति से सम्बन्धित विषयों पर मुक्त विचार-विमर्श का माध्यम।

वार्षिक शुल्क : ४ रुपये

एक प्रति : ६० पैसे

अंक-प्राप्ति के लिए लिखें

“प्रचार निर्देशालय”

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोद्य' इर्ला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ एएस

सामयिक चर्चा

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय : अशान्ति का अखाड़ा

वाराणसी : ११ नवम्बर, '६५। आज सायंकाल वाराणसी के कुछ नागरिकों की सर्व सेवा संघ के राजघाट स्थिति प्रधान कार्यालय में हुई एक बैठक में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की अशान्ति स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ। लम्बी चर्चा के बाद बैठक में भाग लेनेवाले नागरिकों ने अपने सम्मिलित वक्तव्य में कहा कि : "(१) किसी भी शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दलों द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, (२) किसी भी रूप में किसी भी ओर से की गयी हिंसा की खुली निन्दा की जानी चाहिए, (३) शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कर्मचारियों में जो शान्तिप्रिय लोग हैं, उन्हें शिक्षण-संस्थाओं में शान्ति और सौहार्द कायम रखने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए। हम वाराणसी के नागरिक, जो किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखते, और जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की हाल की घटनाओं से अत्यधिक चिन्तित हैं, विश्वविद्यालय के अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकलापों का सुचारु रूप से चलाने के लिए समाधानकारी हल ढूढ़ने के निमित्त निम्न व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करते हैं : डा० रामधर मिश्र, श्री रोहित मेहता, राजा प्रियानन्द प्रसाद सिंह, श्री नारायण देसाई, श्री सुगत दासगुप्ता, श्री वंशीधर श्रीवास्तव (संयोजक)।"

स्मरणीय है कि विगत कुछ महीनों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ है, वह बहुत ही चिन्ताजनक है। विश्वविद्यालय दो गुटों के संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है। एक गुट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जन-संघ के संरक्षण तथा दूसरा समाजवादी और साम्यवादी दलों के समर्थन से शक्ति और प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। समाजवादी प्रभाव-वाले गुट का कहना है कि विश्वविद्यालय के अहाते में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती है, और कुछ छात्र तथा प्राध्यापक नियमित इसमें भाग लेते हैं। स्वयं उपकुल-पति (वर्तमान) भी गुरु गोलवलकर के साथियों में से हैं, और संघ के लोगों को उनसे

विशेष संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता है ; दूसरे गुट का कहना है कि विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करनेवाले बाहरी तत्वों पर रोक लगायी जाय।

आरोप-प्रत्यारोप लगभग एक-से हैं और घात-प्रतिघात के स्वरूप भी समान-से हैं। परिस्थिति अत्यन्त उलझी हुई है। वस्तु-स्थिति का पता लगाना अत्यन्त कठिन है। छात्रों द्वारा हड़ताल, प्रदर्शन, अनशन, धेराव, पथराव से लेकर विश्वविद्यालय के अधिका-रियों द्वारा निन्दा, निष्कासन और पुलिस के दमन-चक्र तक का सिलसिला चला है। और अब सुलझाव के लिए सबकी निगाहें दिल्ली की ओर लगी हैं।

रविशंकर महाराज

अखिल भारतीय अग्रगुप्त समिति

१९६८-६९ के लिए अभ्यर्च

१९६८ अखिल भारतीय अग्रगुप्त सम्मेलन मद्रास में आगामी वर्ष के लिए अखिल भारतीय अग्रगुप्त समिति के अध्यक्ष श्री रविशंकर महाराज निर्वाचित हुए हैं। महाराज ने १९ व्यक्तियों की कार्यसमिति की घोषणा की है।

श्री दातारामजी का प्रयास

सर्वोदय पर्व में कलकत्ता के टाटिया हायर सेकेण्डरी स्कूल में श्री दातारामजी मक्कड़ के प्रयास से सिर्फ दो दिनों में ६० ३६३ ९० का साहित्य बिका। निश्चित तिथि को एक प्रदर्शनी लगायी और दूसरे दिन साहित्य-बिक्री का क्रम चला। स्कूल के बच्चों को मार्गदर्शन के लिए श्री दातारामजी ने सर्वोदय-साहित्य की जानकारी भी दी।

विनोबाजी का कार्यक्रम

नवम्बर, '६५

- १७-१९ अम्बिकापुर, सरगुजा (म० प्र०)
- २० बलरामपुर, सरगुजा (म० प्र०)
- २१ रामानुज गंज, सरगुजा (म० प्र०)
- २२ गढ़वारोड, पलामू (बिहार)

२३ नवम्बर से

२ दिसम्बर '६५ तक डाल्टेनगंज, पलामू।

पता-विनोबा निवास, डाल्टेनगंज,

जि० पलामू (बिहार)

सफाई विद्यालय का अगला सत्र

सफाई विद्यालय, आश्रम पट्टीकल्याणा, जिला करनाल, हरियाणा, प्रान्त का अगला सत्र दिसम्बर '६५ से १५ फरवरी '६६ तक चलेगा। सफाई-काम की वैज्ञानिक जानकारी तथा गोबर-गैस व भंगी-मृत्ति जैसे पवित्र, आध्यात्मिक विषय जानने के इच्छुक भाई प्रार्थना-पत्र भेजकर अपने लिए स्थान सुरक्षित करा लें। समय कम है, अतः शीघ्रता करें। प्रशिक्षार्थी की आयु १८ वर्ष से ४० वर्ष के बीच हो। प्रशिक्षार्थी की योग्यता दसवीं सम-कक्ष की, प्रमाण-पत्रों सहित हो। प्रशिक्षण के पश्चात् काम देने की जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं होगी। प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी रहेगा।

प्रशिक्षण-काल में प्रशिक्षार्थी को विद्यालय की ओर से ६० ६० प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा आने जाने का तीसरे दर्जे का मार्ग-व्यय दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए आचार्य से पत्र-व्यवहार करें।

—महाश्रीर स्यागी

आचार्य,

सफाई विद्यालय,

आश्रम पट्टीकल्याणा

जि० करनाल, हरियाणा

भूल-सुधार

'भूदान-यज्ञ' : अंक ६, दिनांक ११-११-६५; पृष्ठ ७७ के कालम ३ में तीसरी पंक्ति में '६७ की जगह '६५ पढ़ें'। भूल के लिए क्षमा करें।—सं०

वार्षिक शुल्क : १० रु०; विदेश में २० रु०; या २५ शिलिंग या ३ डालर। एक प्रति : २० पैसे।

श्रीकृष्णदत्त भट्ट द्वारा सर्व सेवा संघ के लिए प्रकाशित एवं इण्डियन प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी में मुद्रित।



इस अंक में

‘वोट’ लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और ‘वोट देने वाला’ उसकी बुनियादी इकाई। यह कहने की जरूरत नहीं कि बुनियाद जितनी ही पक्की होगी, इमारत उतनी ही मजबूत होगी। अपने देश में हर बालिग नागरिक के ‘वोट’ से चुने गये प्रतिनिधियों की सरकार बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने देश में ‘जनता का राज’ है। लेकिन क्या जनता यह महसूस करती है कि उसका राज है? ऐसा क्यों है कि ‘जनता का राज’ के नाम पर स्वराज्य के २१ वर्षों बाद भी ‘नेताओं का ही राज’ चल रहा है? क्यों जनता दिनोंदिन असहाय, सरकार की मुंहताज और नेताओं का खिलौना बनती जा रही है?

क्योंकि वोट देनेवाली जनता के इर्दगिर्द तरह-तरह के ऐसे भ्रमजाल फैलाये गये हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार को समझ और पहचान नहीं पाती। नेता तरह-तरह से बहकाकर जनता के दिमाग में यह बात बैठा देते हैं कि जनता का काम है सिर्फ वोट देना, बाकी सारा काम तो नेताओं की सरकार कर ही देगी!

और जनता जब नेताओं के ‘कोरे वादों’ की असलियत पहचान लेती है, और खीझ उठती है; तो जाति-धर्म के नाम पर, भय-लोभ के बल पर, तथा और भी ऐसे ही अनेक निहायत गलत तरीकों से वोट लेने की कोशिश चलती है। परिणाम यह होता है कि गाँव-गाँव में कलह पैदा होता है, और गलत ढंग से वोट हासिल करके जो सरकारें बनती हैं, उनमें गलत लोगों का ही बोलबाला होता है। क्योंकि गलत तरीकों से ‘वोट’ हासिल करके जीतनेवाला गलत कामों का ‘उस्ताद’ होता है, तभी तो वह जीत पाता है! नतीजा यह होता है कि पूरी सरकार ही गलत होती है। गलतियों का यह सिलसिला तो अब यहाँतक बढ़ गया है कि कौन-सी सरकार कब टूट जायेगी, कुछ कहना मुश्किल है।

यही कारण है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और प० बंगाल में पाँच साल की जगह दो साल के ही बाद फिर चुनाव होने जा रहे हैं। ‘वोट’ देनेवाली जनता के सामने फिर सवाल आ गया है कि वोट किसे दें? गाँव-गाँव में पंडित काका के कौड़े से लेकर खेत-खलिहान तक अब यह सवाल चक्कर काट रहा है, ‘वोट किसे दें?’ इसी सवाल पर वोट देने वालों को सोचने और निर्णय लेने में मदद पहुँचाने के लिए ‘गाँव की बात’ का यह मध्यावधि चुनाव-अंक प्रकाशित किया जा रहा है।

— संपादक।

गाँव की बात

पंडित काका का कौड़ा

ठंडक बढ़ती जा रही है। बोआई भी लगभग हो चुकी है। बरसाती फसल में तो भगवान ने साथ नहीं दिया, रबी में देगा या नहीं, कौन जानता है? लेकिन यह किसान ऐसा है कि कभी हार नहीं मानता। प्रकृति और समाज की बराबर मार खाते हुए भी किसान कभी हिम्मत नहीं हारता। खेती किसान के धैर्य और साहस की कहानी है। इतने पर भी जब किसान की हार हो जाती है तो वह मजदूर बनकर जीने की कोशिश करता है। पर यह जान लेने की बात है कि जब किसी देश और समाज में किसान की इस तरह हार होने लगती है कि उसके सामने मजदूर होने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता तो उस देश या समाज को पतन से बचाना बहुत कठिन होता है।

बंसीपुर गांव के हरखू पंडित बहुत पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन अनुभवी आदमी हैं। क्या खेती-बारी, क्या जनम-करम, क्या दवा-दारू, क्या विवाह और श्राद्ध, और क्या पड़ोस के झगड़े और इलाके की राजनीति, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हरखू पंडित की 'तीसरी आंख' से छूट गयी हो। वह हर चीज जानते हैं, समझते हैं, एक-एक बात को गहराई के साथ गांववालों को समझाते हैं।

मौसम देखकर इधर एक हफ्ते से पंडितजी के दरवाजे पर शाम को कौड़ा जलने लगा है। दरवाजा है पंडितजी का, लेकिन कौड़ा सामूहिक है। तापनेवाले अपने-अपने घर से लकड़ी लाकर कौड़े में डालते जाते हैं। कौड़ा भी इतना बड़ा होता है कि एकसाथ चारों ओर बीस-पच्चीस आदमी बैठ लेते हैं। कभी चालीस-पचास तक आ जाते हैं। कौड़ा भी शाम से ११ बजे रात तक अखण्ड जलता है। एक ओर कौड़ा जलता है, दूसरी ओर अखण्ड चर्चा चलती है। पार्क, सिनेमा, क्लब, पाठशाला, जो समझिए, हरखू पंडित का कौड़ा गांववालों के लिए सब कुछ है। और चर्चा भी हर रुचि और हर विषय की होती है।

मौसम की ठंडक भले ही बढ़ती हो, लेकिन राजनीति दिनों दिन गरम हो रही है। वह गरमी धीरे-धीरे गांव-गांव पहुंचने लगी है। चुनाव होगा अभी तीन महीने बाद, लेकिन चुनाव की चर्चा तो शुरू हो ही गयी है। दूसरे लोग चाहे भूल भी जायें, लेकिन मनबहाल चुनाव को नहीं भूलता। घुमा-फिराकर चुनाव की चर्चा छेड़ ही देता है।

'पंडित काका, लगता है इस बार चुनाव फीका रहेगा', चर्चा छेड़ते हुए मनबहाल ने कहा।

'ऐसा क्यों?' चर्चा बढ़ाते हुए पंडित काका ने पूछा।

'चुनाव में मजा तब आता है जब उम्मीदवार घाकड़ होते हैं। अभी उम्मीदवारों के नाम तो तय नहीं हुए हैं, लेकिन जो लोग टिकट के लिए दौड़-धूप कर रहे हैं उनके नाम तो मालूम ही हैं। नाम ही नहीं, गुण, कर्म, सब मालूम हैं। पार्टी चाहे जो हो, पर लोग एक ही तरह के हैं, इनमें कौन किस लायक है?' मनबहाल ने कहा।

'तो इसका मतलब यह हुआ कि लालाजी एक ही हैं, सिर्फ दूकानें अलग-अलग हैं,' पंडितजी बोले।

श्यामधर मास्टर अबतक चुप थे। लालाजी और उनकी दूकान की बात कान में पड़ी तो बोल उठे: 'चुनाव बिलकुल दूकानदारी है और क्या कहा जाय? अपने माल को अच्छा बताकर ग्राहक को ठगना है।'

पंडित काका ने उत्तर दिया: 'होना तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन हो गया है कुछ ऐसा ही। चुनाव में दूकानदारी से बढ़कर पंडागिरी है। जैसे पंडा बात करता है जजमान के कल्याण की, लेकिन उसकी निगाह रहती है जजमान के नोट पर, उसी तरह नेता बात करते हैं हमारी-तुम्हारी भलाई का, लेकिन हरदम निगाह रहती है वोट पर।'

'पंडागिरी की बात खूब कही, पंडित काका', रमई बोला।

इस पर पंडित काका ने समझाना शुरू किया। कहने लगे: 'सब लोग प्रयाग-संगम पर गंगा-स्नान करने तो गये ही हो। वहाँ जाने पर क्या दिखाई देता है? हर पंडे की अलग चौकी रहती है। एक लम्बे बाँस पर उसका अपना झरखा फहराता रहता है। जिस पर उसका निशान बना रहता है। ज्यों ही यात्री दिखाई देता है पंडे एकसाथ चिल्लाने लगते हैं जजमान इधर आओ, जजमान इधर आओ। बोलो रमई, चुनाव के दिन बिलकुल इसी तरह की पंडागिरी होती है या नहीं?'

'आपने तो बिलकुल तस्वीर खींच दी।' तमाखू की फूँक मारते हुए धिरहू ने कहा।

मनबहाल ने चर्चा शुरू तो की थी, लेकिन बीच में वह कुछ नहीं बोला था। सबकी बातें सुनकर जैसे गुनता जा रहा था। अब उससे नहीं रहा गया। कहने लगा: 'पंडित काका ने तस्वीर तो बहुत अच्छी और सही खींची, लेकिन रमई भैया, यह तो सोचो कि इन्हीं पंडों को हम अपना नेता मानते हैं या नहीं? हमारा वोट लेकर ये एम० एल० ए० बनते हैं, मंत्री बनकर हमारे ऊपर हुकूम चलाते हैं और हम गाँव के लोग इन्हें माई-बाप मानकर पीछे-पीछे गिड़गिड़ाते फिरते हैं। जो वोट दे

वह कुछ नहीं, और जो झूठ-सच बोलकर, सही-गलत काम कर, वोट ले, वह नेता, हाकिम—सब कुछ! काशी-प्रयाग का पंडा तो रुपया-दो रुपया लेकर छोड़ देता है, लेकिन ये पंडे तो जैसे हम लोगों को गुलाम बना लेते हैं। अचरज तो यह है कि हम खुशी-खुशी बन भी जाते हैं। इतना ही नहीं, हम इनकी खातिर आपस में लड़ते तक हैं, और जनम-जनम के लिए एक-दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं।

चर्चा धीरे-धीरे गम्भीर हो गयी। मनबहाल की इन बातों ने सबको कुरेद-सा दिया। सब पंडित काका की ओर देखने लगे। उनके अनुभव और बुद्धि पर सबको भरोसा था। सब जानना चाहते थे कि मनबहाल की बातों के बारे में पंडित काका की क्या राय है। पंडित काका चुप थे, लेकिन यह देखकर कि दूसरे नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने शुरू किया : 'भाई, देखो। हम लोगों ने आज तक इस पंडागिरी को, इस हार-जीत को, नेताओं का तमाशा समझा था। अब समझ में आ रहा है कि सचमुच तमाशा यह नहीं है।

'पाँच साल में वोट हो, ढाई साल में वोट हो, हर साल वोट हो, यहाँ तक कि हर महीने होने लगे, तो भी क्या होगा ?

अगर हम इसी तरह वोट के पीछे पागल बने रहे, झण्डों और नारों के पीछे दौड़ते रहे, और चुनाव की आग में गाँव को जलने देते रहे तो मुझे दिखाई देता है कि हम इसी तरह गाफिल बने रहेंगे, और बरबाद हो जायेंगे। अबतक जो हुआ वह हुआ, लेकिन मेरी राय है कि इस बार आप लोग इकट्ठा बैठिये, और सोचिये कि क्या करना है। मनबहाल, जवान लोगों को जरूर इकट्ठा करना। क्या ऐसे मामले पर भी पूरा गाँव एक होकर नहीं सोच सकता है ?'

'क्यों नहीं ? जब आपके समझाने पर हमलोगों ने ग्रामदान के कागज पर दस्तखत कर दिया, तो चुनाव के बारे में तय करने के लिए कौन ऐसा होगा जो आने से इनकार करेगा ?' मनबहाल ने सबकी ओर से कहा।

'क्या हर्ज है ? परसों पूर्णिमा है। खबर करा दो, सब लोग मन्दिर पर इकट्ठा हो जायें। जिसको जो कहना होगा, सबके सामने कहेगा।' रमई ने कहा।

रात काफी जा चुकी थी। सब उठे और अपने-अपने घर की ओर चल पड़े। कई लोग कहते जा रहे थे : 'बैठक में कुछ-न-कुछ तय हो ही जाना चाहिए।'

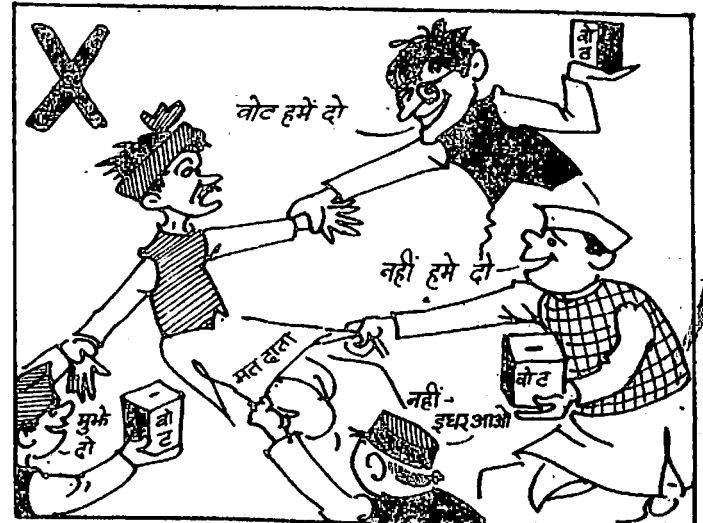
वोट किसको दें ? किसको नहीं दें ?

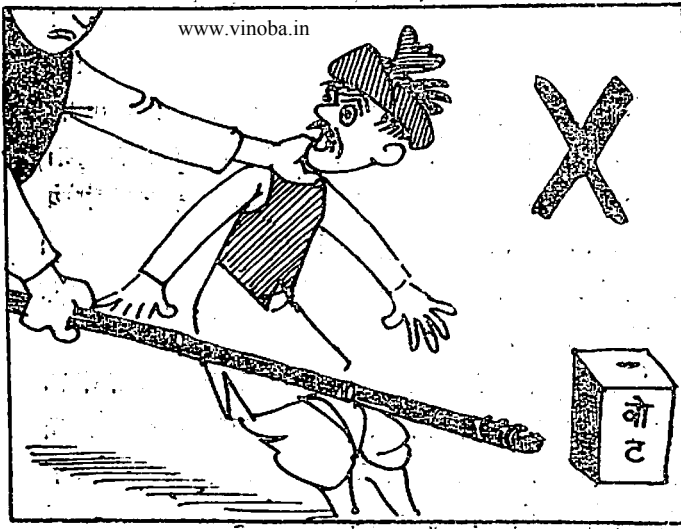
वोट क्या पंडागिरी है !

वोट ! वोट ! वोट ! पहले तो यह आंधी ५ साल पर आती थी, इस बार दो ही साल में आ गयी। अब आगे क्या हर साल चुनाव हुआ करेगा ? कहा जाता था कि चुनाव नहीं होगा तो सरकार कैसे बनेगी ? और अबतक हुआ भी यही कि चुनाव हुआ तो सरकार बनी जो कुछ दिन चली, लेकिन अब तो सरकार के चलने को कौन कहे, उसका बनना भी मुश्किल है। चुने जाने के बाद कौन कितने दिन रहेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं रहा। न किसीकी बात का ठिकाना रहा, न दल का।

वोट क्या पूरी पंडागिरी है। 'हमें वोट दो', 'हमें वोट दो,'—जिघर देखो यही रट है। सोचता हूँ, इस बार किसीको वोट न दूँ। जिसको सरकार में जाना है जाय, नेता बनना है बने, मैं क्यों हैरान होऊँ ? एक दल की, मिले-जुले दलों की, दल-बदल की, सब तरह की सरकारें तो देख ली गयीं, अब किसे देखना बाकी है ? भलाई कुछ नहीं होती, उलटे गाँव-गाँव,

घर-घर में लड़ाई का बीज बोया जाता है। लेकिन फिर सोचता हूँ कि यही तो एक मौका है जब लोग मुझे पूछते हैं, मेरे दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं : 'तुम स्वामी हो, हम सेवक हैं।' और चाहे कुछ हो या न हो, इतना भी कम नहीं है। इसलिए वोट जरूर देना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि किसे दिया जाय ?





ऐसी जबरदस्ती ?

अरे, यह आदमी डंडा दिखाकर वोट लेगा? वोट में भी जबरदस्ती! कहते हैं मतदान है! यह कैसा दान है, जो डंडे से लिया जाता है? डंडेवाले को अपना वोट हरगिज नहीं दूंगा।



वोट भी क्या साग-भाजी है ?

यह नेताजी तो नोट लेकर निकले हैं! सोचते हैं, गरीब है, गरीब की कीमत ही क्या? एक-दो रुपये पायेगा, खुश हो जायेगा। देखता भी है कि कई लोगों ने दिन-रात एक कर रखा है। सुना है हरखू बाबू के मत्थे आज एक महीने से चाय पीयी जा रही है, और दोनों वक्त डटकर भोजन किया जा रहा है! एक दिन रामप्रसाद मुझसे कह रहा था: 'चौधरी, पचीस-पचास जो कहो दिलवा दूँ, लेकिन इस बार पूरे टोले का वोट हरखू बाबू को मिलना चाहिए।' कभी-कभी मन में आता है कि क्या

जाता है अपना। किसीको तो वोट देना ही है, क्यों न सौ रुपये पर सौदा पटा लूँ? रुपया बड़ी चीज है। अच्छा, करूँगा चर्चा रामप्रसाद से।

...लेकिन क्या करूँ, मन नहीं मानता। क्या पचास और क्या सौ, रुपये की बात करना यानी अपने को बेचने की बात करना। होगा अपने घर का सेठ, मैं क्या साग-भाजी हूँ कि बाजार में बिकूँ? क्या गरीब की इज्जत नहीं होती?

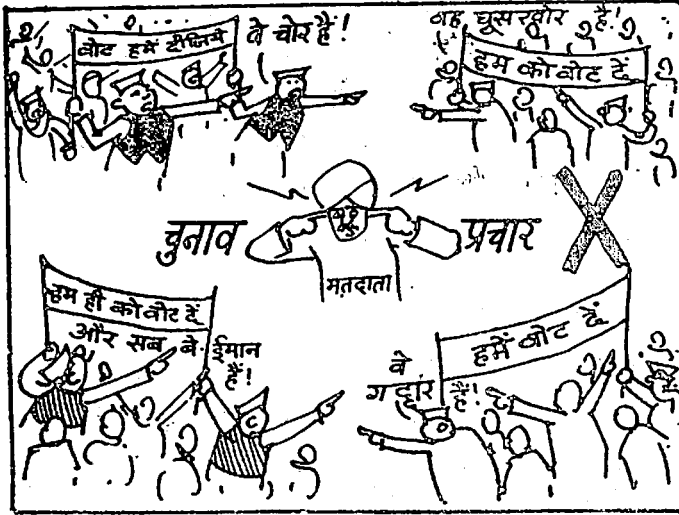


इस बार यह भी ?

इस बार एक नया तमाशा देखने को मिल रहा है। जाति की, धर्म की, पार्टियों की दुहाई तो पहले भी दी जाती थी, लेकिन इस बार इस झुलाके में सवर्ण-अवर्ण की बात जोरों से चल पड़ी है। जब दूसरे धर्मवाले से लड़ाई होती है तो कहा जाता है कि अपने धर्मवाले को वोट देना चाहिए, विधर्मों को नहीं। लेकिन इस बार जब सब उम्मीदवार हिन्दू हैं तो कहा जा रहा है कि हिन्दू हैं तो क्या, सवर्ण सवर्ण हैं, अवर्ण अवर्ण। उस दिन राम अभिलाख आया था तो कह रहा था कि पिछड़ी जातियाँ और हरिजन बहुत दिनों से दबे रहे हैं, अब उन्हें उठना चाहिए, और सरकार पर कब्जा करना चाहिए। पिछड़े लोग, हरिजन लोग, आदिवासी लोग, सब मिल जायें तो उनकी बहुत बड़ी शक्ति हो जायेगी। सवर्णों को दबाने का यही तरीका है।

ठीक है, कहने को बहुत-कुछ कहा जा सकता है। हिन्दू-मुसलमान, सवर्ण-अवर्ण, आदिवासी-गैरआदिवासी, सभी एक-दूसरे के खिलाफ बहुत-कुछ कह सकते हैं। लेकिन सरकार तो सबकी होती है। क्या सरकार भी एक की होगी, दूसरे की नहीं? क्या हमारी जाति का मिनिस्टर होगा तो हम लोगों के नाम हर महीने मनीआर्डर भेजेगा? मैं तो बीस बरस से देख रहा हूँ कि जिसको कुर्सी मिलती है वह कुर्सी का ही हो जाता

है। सभा में खड़े होकर चाहे जो कहे, लेकिन सचमुच वह कुर्सी के सिवाय और कुछ जानता नहीं। उसकी कुर्सी ही उसका ईमान और भगवान बन जाती है। बाकी सब कुछ वह भूल जाता है। और, अगर सरकार में भी जाति और वर्ण और धर्म का भगड़ा छिड़ जाय—दल का तो रहता ही है—तो क्या होगा? किसका भला होगा? जो कुछ बचा है वह भी चौपट हो जायेगा। कुछ भी हो, मुझे जाति, वर्ण आदि की बात नहीं जंचेगी। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा।



कौन भला है ?

मुश्किल तो यह है कि अगर इन बातों को मन से निकाल दिया जाय, तो जाना कैसे जाय, कि कौन अच्छा है, कौन बुरा! चुनाव में सब अपने सिवाय दूसरों को चोर, घूसखोर, बेईमान, गद्दार कहते हैं। जब कान में हर वक्त इसी तरह की बातें पड़ती रहती हैं तो दिमाग काम नहीं करता, जो घबड़ा जाता है। लगता है, जैसे कोई भला आदमी बचा ही नहीं है।

इन बच्चों को तो छोड़ देते !

जब इन भले মানুষों को दूसरे लोग नहीं मिलते तो बच्चों को ही बुला लेते हैं। उन्हीं से नारे लगवाते हैं। बच्चे बेचारे क्या समझें? उन्हें चिल्लाने में मजा आता है। जिसने बुला लिया उसीके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन मेरी समझ में इन बच्चों के दिमाग में अभी से जहर भरना अपराध माना जाना चाहिए। मैं अपने गांव में एक-एक आदमी से कहूंगा कि हम लोग मिलकर गांव में यह सब न होने दें। आखिर, बच्चे इस पचड़े में क्यों पड़ें? क्या हम सयाने लोग बच्चों के चिल्लाने से किसीको वोट देंगे, और किसीको नहीं देंगे?



सब साथ क्यों न आयें ?

इस सारे हल्ले-गुल्ले की जहूरत भी क्या है? क्यों न गांव भर की ओर से सब उम्मीदवारों के पास सन्देश भेज दिया जाय कि हमारे गांव में वोट के लिए जिन नेताओं को आना हो, सब

वोट उसे न दें
जिसकी बात और ईमान का
भरोसा न हो,
जो पैसे की लालच और ढंडे
का डर दिखाता हो;
और जिसका दिल, दिमाग
संकीर्ण हो।

एकसाथ आयें। एक दिन, एक समय आयें, एक मंच पर बैठें, और अपनी बात कहें, और एक बार कहकर हम लोगों को आपस में तय करने दें।



अपनी बात कहिए, और हमें छोड़िए

बड़ा अच्छा है। एक मंच पर कई दलों के नेता बैठे हैं। अब घंटे-दो घंटे घुम्राधार भाषण होंगे। हम लोग सबकी बात सुनेंगे सवाल पूछेंगे कि चुन लिये जाने पर कौन गाँव के लिए क्या करेगा, सबकी बात समझेंगे, और अन्त में सबको खिला-पिलाकर आदर के साथ विदा करेंगे। तय तो गाँव को करना है, रोज-रोज हल्ला-गुल्ला मचाने की क्या जरूरत है ?



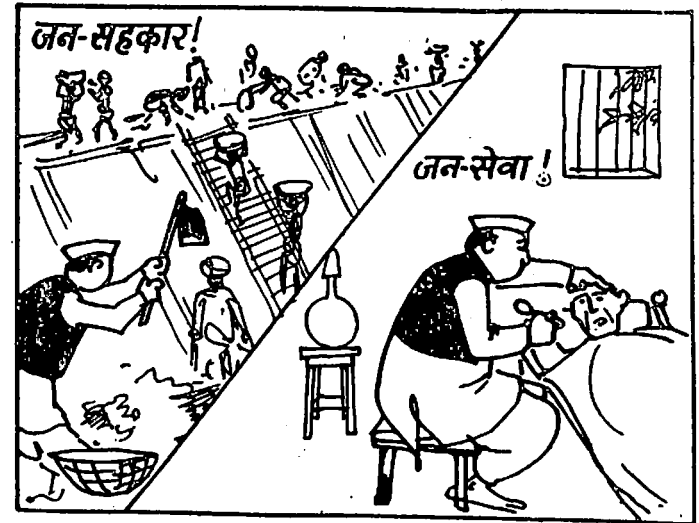
कुछ भी हो, गाँव की एकता न टूटे

चुनाव आया है, एक दिन खत्म हो जायेगा, लेकिन अगर गाँव में आदमी-आदमी के, जाति-जाति के, वर्ण-वर्ण के, या दल-

दल के बीच दुश्मनी का बीज बो गया तो क्या होगा ? हमें तो गाँव में ही रहना है। क्या आपस में लड़ मरना है ? पड़ोसी-पड़ोसी का भगड़ा-रगड़ा बनकर दोनों को खा जाता है। जब हम गाँव में ही, जहाँ हमें और हमारे बाल-बच्चों को रहना है, एक-दूसरे के दुश्मन हो जायेंगे, तो कोई भी जीते, किसीकी भी सरकार बने, हमारे गाँव की तो हार हो ही जायेगी। हम अपने गाँव को क्यों बरबाद होने दें ?

गाँव को चुनाव की आग से बचाने का एक अच्छा उपाय यह है कि गाँव के लोग आपस में तय कर लें कि किसे वोट देना चाहिए। जब पूरा गाँव बैठेगा तो सिवाय इसके दूसरा क्या फैसला करेगा कि वोट सबसे अच्छे आदमी को दिया जाय, चाहे वह किसी जाति का, दल का, वर्ण का हो। आदमी की अच्छाई-बुराई का उसकी जाति, वर्ण, दल आदि से क्या सम्बन्ध है ?

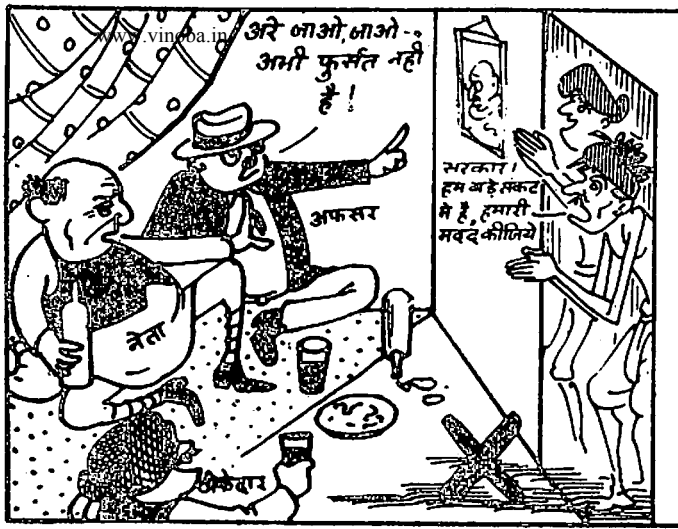
लेकिन हो सकता है कि गाँव के सब लोग एक राय के न हों। तब यह छूट देनी पड़ेगी कि जो जिसे अच्छा समझे, उसे वोट दे, लेकिन गाँव में 'कन्वेंसिंग' आदि न हो और पैसा का लोभ या डंडे का डर न दिखाया जाय। सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाय, जो जिसको चाहे वोट के दिन जाकर चुपके से वोट दे आये। इस तरह मतदान भी स्वतंत्र होगा, और गाँव की एकता भी बच जायेगी, जो सबसे कीमती चीज है।



तो अच्छा किसे मानें ?

माई, अच्छा वह है जो दुखी की सेवा करता हो, और जो अपने क्षेत्र के सामान्य लोगों के साथ मिलकर पसीना बहाता हो।

पार्टी या पड़ोसी, कौन ज्यादा प्रिय हैं ?
पार्टी से गाँव टूटेगा, पड़ोसी से गाँव बनेगा, देश बचेगा !



खूब तिगड़ा है !

उसे अच्छा नहीं माना जा सकता, जिसे गरीब की बात सुनने की फुरसत न हो। और, न तो वह अच्छा माना जायेगा जो शराब की मौज लेता हो और दिन-रात अपना ही उल्लू सीधा करने में लगा रहता हो। आज जहाँ देखिए, इसी तरह के लोग आगे दिखाई देते हैं। इनसे भगवान बचाये !



अरे, ग्रामदान के नाम में अंगूठा !

उस दिन गाँव के मुखियाजी राम गोपाल बाबू के दरवाजे पर ग्रामदान का कागज लेकर गये तो उनकी ल्यौरी चढ़ गयी, और अंगूठा दिखाते हुए बोले : 'जाइए मुखियाजी, मैं इस प्रपंच में नहीं पड़ता। जमीन बड़ी मुश्किल से कमायी जाती है।' सोचने की बात है कि जो आदमी गाँव की भलाई और संगठन की बात भी न सुनना चाहता हो, उसको भी भला कोई वोट देगा ?

१८ नवम्बर, '६८]



बेदखली भी, और वोट भी ?

यही हाल उसका है जो बेदखली करता है। जो गरीब के हाथ से उसकी जीविका का सहारा छीनता हो, उसे क्या अधिकार है वोट की बात करने का ?



दिल और दिमाग नया हो

सचमुच अच्छा वह है जिसका दिल और दिमाग नया हो, जो गाँव की बात सोचता हो, जो गाँव के साथ रहने और काम करने को तैयार हो। ग्रामदान में शरीक होना अच्छाई का एक बहुत बड़ा प्रमाण है।

वोट उसे न दें

जो शराब पीता हो, छुआछूत मानता हो;
जो ग्रामदान में शरीक न हुआ हो।



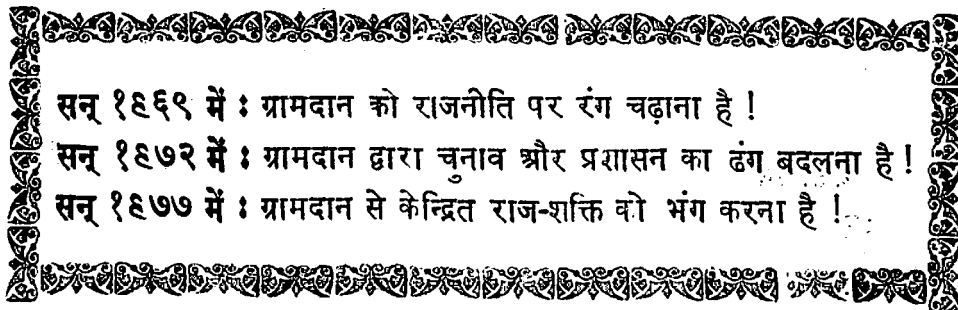
पड़ोसी हमारा भाई

जो ग्रामदान को समझ जाता है वह भूमि से ज्यादा कीमत पड़ोसी की मानता है। जिसने अपने हृदय में मनुष्य को स्थान दे दिया उसके अन्दर और अच्छाइयाँ अपने-आप आ जायेंगी।



वोट उसे दें

जो सच्चरित्र हो, चुनाव में ईमानदार हो,
जो दल-बदल न करता हो;
जो सेवाभावी हो, बेदखली न करता हो;
जो छुआछूत और जातिवाद को बढ़ावा न देता हो;
जो ग्रामदान में शरीक हुआ हो;
जिसके विचार नये हों,
और
जो मनुष्य की मनुष्य के नाते कद्र करता हो।



‘गाँव की बात’ : वार्षिक चन्द्रा : चार रुपये, एक प्रति : अठारह पैसे।

श्रीकृष्णदत्त भट्ट द्वारा सर्व सेवा संघ के लिए प्रकाशित और इंडियन प्रेस (प्रा०) लि०, धाराणसी में मुद्रित।